[श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

अच्छा होता कि माननीय सदस्य पहले से ही इस आशय की सूचना कार्यालय को दे देते और कार्यालय हम को इस बात की सूचना देता कि यह एड्जार्नमेंट वाले बिल हैं और आगे डिसकशन के लिये जाने वाले हैं जिससे कि जितने भी माननीय सदस्य हैं वे अगले, पांचवें बिल की, तैयारी करके आएं। उपसभापति महोदया, वैसे ही चार बिलों का अध्ययन करना और चार बिलों को एकदम ड्राप करना और पांचवें बिल का चर्चा के लिये आना, जरा ऐसा लगता है कि मानवीय शक्ति के आधार पर बिल्कुल असम्भव सा है कि हम ऐसा कर सकें। फिर भी माननीय सदस्य जब स्वयं चाहते हैं कि ये एड्जार्न किये जायें तो मैं उस पर आपत्ति तो नहीं कर सकता परन्तु यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में अगर इस तरह से वापस लेने की प्रार्थना कोई सदस्य करे, या इस तरह की रिक्वेस्ट करे, तो उसके पहले या तो वह सफिशियेन्ट नोटिस हाउस को कार्यालय की मार्फत दिलवा दे नहीं तो वापस लेने का अधिकार भविष्य में नहीं दिया जाना चाहिये।

SHRI M. P. BHARGAVA : Madam, my hon. friend, Shri Chordia, has raised not exactly an objection but he has raised certain points. I do agree with him that this adjournment notice should have been given earlier. But there were some special circumstances and, therefore, I have come with this motion before the House.

SHRI V. M. CHORDIA: What are those special circumstances? Please narrate.

SHRI M. P. BHARGAVA: I may take the House into confidence and say that the Government is considering the acceptance of most of the amendments in these four Bills, but they want a little more time to study the exact wordings of the clauses in those Bills. Therefore, I have come to the House with this request for adjournment of the debate on these four Bills.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the debate on the following Bills:—

1. The Major Port Trusts (Amend ment) Bill, 1964,
2. The Calcutta Port (Amendment) Bill, 1964,
3. The Bombay Port Trust (Amendment) Bill, 1964, and
4. The Madras Port Trust (Ann ment) Bill, 1964 be

adjourned to a later .date." *The motion was adopted.*

THE INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 1963

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab) Madam, I have great pleasure in moving the motion for reference of the Indian Pen;il Code (Amendment) Bill, 1963 to a Select Committee. I^[want your permission, Madam, not to move the motion for reference of the Bill to a Joint Select Committee, but only to a Select Committee of this House. Therefore, I beg to move: \

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members:—

Shri Akbar Ali Khan,

Shri M. P. Bhargava,

Pandit S. S. N. Tankha,

Shri Arjun Arora,

Shri M. M. Dharia,

Shri Bhupesh Gupta,

Shri Mulka Govinda Reddy,

Shri Ganga Sharan Sinha,

Shri Dahyabhai V. Pate!,

Shri K. K. Shah,

Shri P. K. Kumaran,

Shri Jaisukhlal Hathi,

Shri A. D. Mani,

Shri Sitaram Jaipuria, and

Diwan Chaman Lall (the mover)

with instructions to report by the first day of the next session."

The question was proposed.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, हमारे मित्र दिवान चमनलाल जी ने जो यह बिल रखा है, वह यद्यपि सिलेक्ट कमेटी के पास जा रहा है, तथापि उन सदस्यों के सामने विचारार्थ कुछ सामान हो इसलिये मैं इस संबंध में कुछ निवेदन करना आवश्यक समझता हूं। हमारे माननीय मित्र ने धारा 293, भारतीय दंड संहिता के आगे एक और धारा 293 ए जोड़ने के लिये प्रस्ताव किया है। उसमें यह बताया गया है कि :

"Nothing contained in section 292 or section 293 shall apply to any book, pamphlet, writing, drawing, painting, representation or figure meant for public good or for *bona fide* purposes of science, literature, art or any other branch of learning:

Provided that in the event of any dispute arising as to the nature of the publication, the opinion of experts on the subject may be admitted as evidence."

जो यह बिल रखा है इस का मैं दो कारणों से विरोध करता हूं और वह विरोध करने के कारण यह हैं कि भारतीय दंड संहिता के लिये और भारत में जितने भी क्राइम्स हों उन के लिये क्या प्रोसीजर हो, या व्याख्या हो, इसके लिये अलग कानून है। और कानून में क्या एविडेन्स दी जाय इसके लिये एविडेन्स ऐक्ट है। तो दूसरा जो प्राविजो है वह अपने आप में पूर्ण नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात, अगर हमारे मित्र दिवान चमनलाल जी यह समझते हैं कि इसके द्वारा वे राष्ट्र का बहुत कुछ भला करेंगे, तो मैं समझता हूं वह इसमें विशेष सफल होने वाले नहीं हैं। यह हम जानते हैं कि दिवान चमनलाल जी संसार का भ्रमण किये हुये व्यक्ति हैं, संसार की बहुत सी सभ्यता और संस्कृतियों का उन्होंने गहरा अध्ययन किया है और यही कारण है कि उनके मस्तिष्क में संसार के दूसरे समाज, देश, सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव पड़ा है और इसी कारण वे समझते हों कि इस प्रकार का विधेयक यहां लाया जाना चाहिये जिसके अनुसार अपने यहां जो कुछ है उसमें आने के लिए और कुछ द्वार आगे के लिये खोला जाय। तो मैं समझता हूं कि अगर संस्कृति के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, आर्ट और लिटरेचर के नाम पर, यदि हम इस प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था कर देंगे तो निश्चित रूप से वह कानूनी व्यवस्था अपने आप में अपूर्ण होगी। उस समय जबकि देश में उच्छृंखलता बहुत अधिक चल रही है और अपने देश में इस समय जो उच्छृंखलता है वैसी बहुत कम पिछले समय में देखने में आई है। पिछले समय जब यह बिल प्रस्तुत हुआ था तो उस समय कई मित्रों ने यह बातें बतलाई थीं और बहुत से मित्रों ने कहा था कि हमारे यहां संस्कृति में इस 'आब्सीन' प्रकार की चीजें मौजूद हैं। मंदिरों में इस प्रकार के चित्र हैं, मंदिरों में इस प्रकार की लेखानुकृतियां हैं और इस प्रकार के दूसरे कारण हैं कि हम उन पर आगे विचार कर सकते हैं तथा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं नम्र निवेदन करूंगा कि हमारे यहां इस प्रकार के जितने भी सांस्कृतिक रूप हैं, उसमें कुछ न कुछ ऐसी आड़ या मर्यादाएं रखी गई हैं जिस के कारण कोई व्यक्ति यदि वह सदाचार से संबंधित नहीं है तो उसका प्रश्रय या लाभ ले सकता है। उदाहरण के लिये अगर कहीं पर कोई नग्न चित्र बतलाया गया है तो उसका आशय यह कदापि नहीं लेना चाहिये कि कोई व्यक्ति उसका कोई भिन्न आशय लेगा क्योंकि उन चित्रों की परिव्याख्या मंदिरों के होने के कारण उसका धार्मिक आड़ या मर्यादा उसके सामने आ जाती है। इसलिए इसका दूसरा लाभ नहीं ले सकता है। ठीक इसी प्रकार चित्रकला के संबंध में हमारे देश से दूसरे देशों की तुलना नहीं की जा सकती है।

हमारे यहां अपने देश की संस्कृति है, अपने देश की सभ्यता अलग है और उस सभ्यता और संस्कृति को न आप पश्चिमी दिशा में बदल सकते हैं, न उनके मुकाबले में ला सकते हैं। पश्चिमी संस्कृति बिल्कुल अलग है। पश्चिमी देशों में वहां जिस प्रकार की मर्यादा

[श्री निरंजन वर्मा]

चालू है, वही सहन की जा सकती है। मगर वही मर्यादा हमारे देश में रख दी जाए तो निश्चित रूप से हमारा समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकेगा। देश, समाज और व्यवस्था के अनुरूप अलग-अलग कलायें होती हैं। हमारे बहुत से मित्रों ने यह कहा कि हमारे आर्ट और लिटरेचर में पहले भी कुछ ऐसी बातें थीं, तो हम निवेदन करेंगे कि जैसे बंगला में गीत-गोविन्द काव्य शृंगार रस प्रधान है ठीक उसी प्रकार हमारे यहां और भी हिन्दी साहित्य में बिहारी, गंग और इसी प्रकार के कवि हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। रामायण और महाभारत में भी आलाप संलाप है, जहां पति पत्नी बैठकर आपस में चिन्तन करते हैं और इसी प्रकार भर्तृहरि शतक में सबसे अधिक शृंगार लिखा गया है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें मर्यादा से बंधी हुई हैं और वह मर्यादाएं इस प्रकार हैं कि अगर उनके सामने धार्मिक बंधन न हो तो उनसे लोग किसी न किसी प्रकार अनुचित लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे समाज में नंगे व्यक्तियों का परिचलन भी मौजूद है। हमारे जैन समाज में, नागाओं में, बहुत से स्थानों पर बहुत से व्यक्ति नंगे निकलते हैं, लेकिन उनमें एक आड़ है, एक मर्यादा है और वह मर्यादा धार्मिक है जिसकी वजह से कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है और न ही कोई उनकी नकल करने या अनुचित लाभ उठाने का साहस या दुस्साहस ही कर सकता है।

महोदया, इस समय जब कि समाज अत्यन्त नीचे स्तर पर जा रहा है, हमारे छात्र छात्राओं का जीवन इस प्रकार चल रहा है, जिसके कारण लोग उसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं। सिनेमा का इतना अधिक प्रचार है जिसके कारण गत 10 वर्षों में अपने देश में उनकी तरफ अंगुली उठाई जा रही है, उनके पोस्टरों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनके जितने भी पोस्टर होते हैं वे कामोत्तेजनात्मक सामग्री लिये होते हैं जिसके कारण भले समाज के युवक तथा युवतियों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस समय हमारे देश में बाहर से कई प्रकार के नाटककार आते हैं, अपने देश में बाहर के कई तरह के चित्र आते हैं और जब इनका प्रदर्शन होता है तो अपने समाज में बहुत से व्यक्ति उसको पसंद नहीं करते हैं। अभी पिछले समय कुछ चलचित्र ऐसे आये जैसे उदाहरण के लिये टोकियो इन नाइट, पेरिस बाई नाइट, न्यूयार्क बाई नाइट और लन्दन बाई नाइट इस प्रकार के जो चलचित्र चल रहे हैं उनमें बहुत ऑब्सीन और अत्यन्त गन्दगी से भरे हुए दृश्य होते हैं और ये चित्र भी अत्यन्त खराब हैं। अगर श्री दिवान चमन लाल जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए और इंडियन कोड की वह सही धारा छोड़ दी जाए, तो हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्रय उन लोगों को मिलेगा जो इस समाज पर विवेक का अंकुश निकालने के लिये व्यग्र रहते हैं। वकीलों की सहायता से भी इस तरह के दोषों को नहीं बचाया जा सकेगा और इस प्रकार के आचरण करने वाले लोगों को दंडित नहीं किया जा सकेगा जो किसी न किसी रूप में इस बिल का प्रश्रय लेंगे। इसलिए अपने यहां पर, अपने समाज का जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें इस तरह की कामोत्तेजनात्मक भावना फैलाना यह अच्छी बात नहीं है और इस तरह की कार्यवाही को रोका जाना चाहिये तथा उसका बहिष्कार किया जाना चाहिये। यहीं नहीं, बहुत से स्थानों पर ऐसी कलाओं के विरुद्ध परिपाटी चल रही है जैसे रूस के प्रदेश में इस समय कुछ आयु के युवक और युवतियों को एक साथ पढ़ने पर प्रतिबन्ध लगा है, ठीक इसी प्रकार दूसरे देश हैं, जिन देशों में इस प्रकार की चीज के लिए कई बंधन लग गये हैं क्योंकि वहां का जो समाज है वह हमसे कुछ आगे बढ़ गया है और वहां की मर्यादाएं कुछ आगे बढ़ गई हैं। भारतवर्ष का वर्तमान

स्वरूप इस समय जो है, उसमें हमारे युवक तथा युवतियों का स्तर गिरने की सम्भावना है, अगर हम इस तरह से उन्हें कानून द्वारा छूट दे दें और मर्यादाओं को हटा न दें। अगर हमने इस तरह के बंधनों को हटा दिया तो चाहे भले आदमी और समाज के विवेकी मनुष्य तो उसका लाभ न उठा पायेंगे, लेकिन जो बुरे व्यक्ति हैं वे समाज का नुकसान करेंगे, ऐसी हमारी धारणा है।

पिछले समय जब हमारे मित्र ने यह बिल प्रस्तुत किया था तो उन्होंने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में यह दिया था :

"Under the present section 292 and 293 of the Indian Penal Code, there is a danger of publications meant for public good or for *hona fide* purposes of science, literature, art, or any other branch of learning being declared as obscene literature as there is no specific provision in the Act for exempting them from the operation of those sections. The Bill seeks to remove that lacuna so as to bring the law into conformity with modern practice in other civilised countries."

ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे मित्र के हृदय में सद्भावना है और हो सकती है। लेकिन हमारे मित्र ने यह विचार करने का कष्ट नहीं किया कि उनकी सद्भावना शायद वह न समझते हों, ऐसा मैं नहीं मानता हूं— कितनी दूसरी दुर्भावनाएं उत्पन्न कर सकती हैं और लोग इसका कितना अनुचित लाभ उठा सकते हैं। उनके सामने भी बहुत से प्रकरण हैं कि जो छोटे-छोटे बालक हैं अगर संस्कृति के नाम पर, आर्ट के नाम पर, लिटरेचर के नाम पर, साइन्स के नाम पर, कला के नाम पर उन्हें बुरी-बुरी पुस्तकें तथा चित्र दे दिये जायं, तो हम समझते हैं कि हमारा समाज निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकेगा और हमारे समाज का स्तर नीचे गिरते चला जायेगा। अगर शासन उन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाना चाहेगा तो 293 ए बाधक हो जायेगा। और उसके साथ-साथ दंड बाधक सिद्ध होगा जो लोग इस तरह की बुरी हरकत करते हैं। इस प्रकार हमारे मित्र ने संशोधन के लिए जो धारा रखी है, हम समझते हैं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और 293 के पश्चात् 293 अ किसी प्रकार नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ हमारे मित्र ने जो बिल प्रस्तुत किया है, हम उसका विरोध करते हैं।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. S. NASKAR): Madam, the present Bill, (hat is, the Indian Penal Code (Amendmcn!) Bill, 1963, tabled by Diwan Chaman Lall proposes to exclude the applicability of sections 292 and 293 of the Indian Penal Code to any publication meant for public good or for *bona fide* purposes of science, literature or any other branch of learning and also to admit as evidence the opinion of experts on the subject as to the nature of the publication. It has been stated in the Statement of Objects and Reasons of the Bill that the proposed measure is intended to bring the law into conformity with modern practice in other civilised countries.

Section 292 of the Indian Penal Code makes the sale, letting to hire, distribution, public exhibition or circulation of any obscene object or the production or possession or import or export or conveying or advertising of any such object for the above mentioned purposes or taking part or receiving profit from any such business etc. a cognisable offence punishable with imprisonment up tot hree months or with fine or with both. Section 293 of the Indian Penal Code enhances the punishment up to 6 month's imprisonment or with fine or with both when any obscene object is sold, let to hire, distributed, exhibited or circulated to any person under the age of 20 years. Sections 292 and 293, IPC, do not, however, stipulate the test of obscenity. In interpreting the statute, Justice Cockburn in Hicklin's case laid down the following test of obscene literature:-

"A writing was said to be obscene where there was a tendency to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences and into whose

*[Shri P. S. Noskor.] hands the publication of this sort may fall." Indian courts have, in the past, based their decisions on the test laid in Hicklin's judgment.

This test of obscenity has been regarded with great dissatisfaction by authors, publishers and booksellers. Their main charges against it are:

(a) the law does not draw any distinction between pornography ("dirt for dirt's sake") and obscene matter which has literary or artistic worth, and

(b) the Court is not bound to admit as evidence expert opinion on the literary or other worth of the publication charged as obscene.

It has also been held by them that the Hicklin's test curtails the freedom of expression of the writer and the artist and that the law is not in conformity with the conditions obtaining in the modern times. Accordingly, in the United Kingdom, the law regarding obscenity was amended by the Obscene Publications Act, 1959, popularly known as the Jenkins Act. By this Act the court is now required:—

(i) to take into consideration the dominant effect of the whole book;

07) to find whether the publication of the matter is justified on the ground that it is in tha interest of science, literature or learning and of other subjects of general concern; and

(Hi) to admit opinion of the experts as to the literary, scientific or other merits of the publication.

The Bill introduced by Diwan Chaman Lall is aimed substantially to have the same effect.

The Supreme Court of India, while adjudging the obscenity of the book entitled "Lady Chatterley's Lover" by D. H. Lawrence, in their judgment delivered on 19th August, 1964, upheld the Hicklin test, relating to obscenity. That Court further observed as follows:

... we can only say that where obscenity and art arc mixed, art must be so preponderating as to throw the obscenity into a shadow or the obscenity so trivial and insignificant that it can have no effect and may be overlooked. In other words, treating with sex in a manner offensive to public decency and morality (and these arc the words of our Fundamental Law), judged of by our national standards and considered likely to pander to lascivious, prurient or sexually precocious minds, must determine the result. We need not attempt to bowdlcrise all literature ami thus rob speech and expression of freedom. A. balance should be maintained between freedom of speech and expression and public decency and morality but when the latter is substantially transgressed the former must give way."

This means that courts in India are already of the place of art in social life and it is unlikely that a court in India, in view of the above ruling of the Supreme Court, will hold a piece of art etc. where art preponderates to an extent to throw obscenity into the background, as obscene.

The Supreme Court further attempted the following definition of obscenity:

"In our opinion, the test to adopt in our country (regard being had to our community *mores)* is that obscenity without a preponderating social purpose or profit cannot have the constitutional protection of free speech and expression and obscenity is treating with sex in a manner appealing to the carnal side of human nature, or having that tendency. Such a treating with sex is offensive to modesty and decency but the extent of such appeal in a particular book, etc. are matters for consideration in each individual case."

Noticing the increasing tendency in certain quarters to make easy money by publishing indecent material which sometimes borders on obscenity, but would not fall clearly within the ambit of law, and also observing the recent mushroom production of periodicals publishing mostly material catering to prurient taste, the Home Ministry examined the whole matter afresh and decided to undertake Central legislation on the subject through an official Bill. Until the Government intend to bring in legislation, I would not like to oppose the motion to refer the Bill to a Select Committee at this stage.

Thank you.

DIWAN CHAMAN LALL: May I have your permission to say a word or two, after

the two speeches that have been made? One of my hon. friends, Mr. Varma, has made a very fine speech indeed, but unfortunately his speech was conservative. His speech verges on conservatism. He is concerned mostly with the law as it is, as my friend, the Minister was concerned with the law as it is. May I say in regard to the law as it is that I entirely agree with the judgment that has been delivered by the Supreme Court in the case of "Lady Chatterley's Lover"? I also know that there was a judgment by Lord Cockburn in regard to this matter, which was the basis of the law until 1959 in Great Britain. The Bill that was originally moved in the year 1924 was called the Obscene Publications Bill, which is the basis of section 293 of the Indian Penal Code. At that time I happened to be a member of the Legislature, 42 years ago. It was a long time ago and I raised this very matter, namely, the protection that should be given to works of art and literature. When a Third Class Magistrate deals with a matter of this description, he is absolutely unaware of the implications of the action that he takes in proscribing works of art and literature. It is because of that we find this state of affairs in Great Britain and we had followed in our Obscene Publications Bill, practically word for word, the same thing as the English law on the subjects. We have not moved, as Great Britain has moved on towards another base, namely, the base of exempting works of art and literature from the purview of the Obscene Publications Act as Great Britain has done in the year 1959, as stated by my learned friend, the Minister.

Now, what has happened is this. Here in India "Lady Chatterley's Lover" has been banned, banned by the Supreme Court, banned by the lower courts. When the appeal went up to the Supreme Court, the Supreme Court merely corffirmed the decisions that had been arrived at by the lower courts. This is exactly the warning that I gave 42 years ago in regard to this particular measure that the lower courts in India are run by incompetent people, who are not competent enough to deal with the matter of art and literature. They do not know what art and literature means. They do not know the modern implications of art and literature. They are not supposed to know the modern implications of art and literature. Therefore, I am very grateful to my hon. friend, the Minister, for stating that the Government themselves are considering bringing before this House and the other House a measure to amend section 293 of the Indian Penal Code. Until that moment, my hon. friend says he has no objection to this matter going before the Committee that I have named, a Select Committee of fifteen Members, including myself, which will sit and consider the various points that have been raised by my learned friend, Mr. Varma. It will consider also whether in view of the existence in India of a free society—examples were given by Mr. Varma himself—today in that free society any Magistrate can come forward and implicate any of those works of art and literature which he named as being obscene, and they would be considered to be obscene. There is nothing in the law today to prevent a Magistrate from saying that either those paintings in the temples are obscene or—let us go to Konarak and see the sculptures there, and today if a Magistrate were seized of this particular matter, he would consider those to be utterly obscene and capable of being destroyed.

श्री निरंजन वर्मा : मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि उन्होंने सम्भवत: 292 का एक्सेप्शन नहीं देखा। देखा तो अवश्य होगा, शायद उस-की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें महोदया इस प्रकार का उल्लेख है कि अगर कहीं पर ऐसी बात आ जाय जिस पर धार्मिक दृष्टि से विचार किया जा सकता है तो अब उन्हें किसी प्रकार से प्रतिबन्धित नहीं किया जाना चाहिए।

DIWAN CHAMAN LALL: He is quite right. My learned friend talks about religion only. I am talking of a wider aspect than religion. The question is of literature. "Lady Chatterley" was not known at that particular time when this Bill was moved and when I spoke against the proposition that Mr. Mohammad Ali Jinnah at that time stated. At that time "Lady Chatterley" was not known. Now "Lady Chatterley" has been proscribed in India although under the new provisions of the law in Great Britain "Lady Chatterley" has been accepted as a legal thing, as something that is available for literature and is considered good as far a$_g$

[Diwan Chaman Lall.] literature is concerned. On the other hand "Fanny Hill" has been declared to be obscene on the part of the same people, the same Justices, practically the Mime Justices who considered the question of "Lady Chatterley," but they consider that "Fanny Hill" is obscene. One can differ. My hon. friend and I can differ about this matter. As a matter of fact the Leader of the House told me only a couple of days ago that he had a last chat with the late Pandit Jawahar-lal Nehru, Prime Minister of India. The Prime Minister told him that in his opinion "Fanny Hill" was not obscene but that "Lady Chatterley" was obscene. This is the opinion of a very learned man, a very modern-minded man unlike my friend sitting over there, a very modern-minded individual who realised that the world was marching ahead. This is his opinion. I think it is a wrong opinion. 1 do not agree with that opinion. I think it is correct that "Fanny Hill" is obscene and "Lady Chatterley" is not obscene, and it is in order to bring this law in conformity with the existing practice in Great Britain that I want this particular amendment to be referred to the Select Committee. The Select Committee will have the advice of my hon. friend, Mr. Hathi, who is also a member of that Committee, and they will have the advice of the legal luminaries and advice of Ministry in regard to this matter.

Therefore, Madam, I commend this particular motion before you.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill furthei to amend the Indian Penal Code be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members- -

Shri Akbar Ali Khan.

Shri M. P. Bhargava,

Pandit S. S. N. Tankha,

Shri Arjun Arora,

Shri M. M. Dharia,

Shri Bhupesh Gupta,

Shri Mulka Govinda Reddy,

Shri Ganga Sharan Sinha,

Shri Dahyabhai V. Patel,

Shri K. K. Shah,

Shri P. K. Kumaran,

Shri Jaisukhlal Hathi,

Shri A. D. Mani,

Shri Sitaram Jaipuria, and

Diwan Chaman Lall, the mover;

with instructions to report by the first day of the next session."

The motion was adopted.

THE MEMBERS OF PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURES (1MMU- i N1TY FROM DETENTION) BILL, 1964.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Madam, I beg to move:

"That the Bill to provide for immunity to Members of Parliament and State Legislatures from detention without trial be taken into consideration."

Now I am very happy that I have got a chance after so many months of waiting I o move this particular Bill for consideration of this House. This is a very simple Bill if I may use the words of our Ministers but it is certainly politically and constitutionally very difficult from the point of view of the working of parliamentary institutions and of democracy in India. I shall have to deal with it historically and I will also have to refer to certain recent cases to point out why a legislation of this kind today in the country is called for.

Madam Deputy Chairman, if we go back to the prc-independence era, we had some kind of truncated unicameral legislatures functioning in our country and we used those institutions to fight the alien rule to defend the interests of the people and, by and large, served what we thought was the national cause *of* independence. At that time the British Government adopted an attitude of hostility towards those who were fighting in the legislative front like my esteemed friend, Diwan Chaman Lall when he was a member of the Swaraj Party, now of the Congress Parliamentary Party. At that time they enjoyed no immunity whatsoever. At any time the Members of Parliament or the Central Legislative Assembly as it used to be called or the Prorineial Councils, M. L. Cs. as they used to be called, could be arrested and